(c) The inclusion/exclusion of bulk drugs under price control under DPCO 1987 is mainly based on the recommendations made by the Kelkar Committee in its main as well as supplementary report.

(d) and (e) The representations with regard to inclusion/exclusion of bulk drugs under price control (including Tinidazole) are under examination of Government.

Setting up a National Cable Authority

744. SHRIMATI RATAN KUMARI :
SHRI BEKAL UTSAHI :
DR. RATNAKAR PANDEY :

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to set up a National Cable Authority to provide licence and regulate the growth of Cable TV in the country; and

(b) if so, the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI GIRIJA VYAS) : (a) and (b). No, Sir. This is, however, one of the recommendations made by the Inter-Departmental Committee set up to look into various aspects of Cable TV Networks and Dish-Antennae Systems.

People below Poverty Line

745. SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL :
MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI :

Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state :

(a) the number of people living below the poverty line in the country at present;

(b) whether there has been any decline in the number of people living below the poverty line during the last three years; and if so, details thereof; and

(c) the percentage of Muslims out of the total Muslim population who are living below poverty line at present State-wise details thereof ?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI H. R. BHARDWAJ) : (a) In 1987-88, the latest year for which information is available, the number of people living below poverty line in the country was 2376.7 lakh.

(b) Information on the number of people living below poverty line for the years later than 1987-88 is not available.

(c) Estimates of percentage of population living below poverty line on the basis of sects are not collected.

सीमेंट उद्योग को यातायात संबंधी सुविधाओं की अनुपलब्धता

746. श्री राम जेठमलानी :
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 जुलाई, 1991 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में "सीमेंट मूवमेंट थ्रो रेल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तो क्या यह सच है कि रेलवे द्वारा उचित यातायात सुविधायें उपलब्ध न कराये जाने के कारण सीमेंट उद्योग अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं कर सका;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने अपने स्तर पर रेल विभाग से इस संबंध में कोई संपर्क स्थापित किया है ; और

(घ) यदि हां, तो कब और इस संबंध में कठिनाईयों को दूर करने के लिये क्या क्या निर्देश जारी किये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०जे० कुरियन) : (क) जी, हां ।

(ख) कुछ सीमेंट संयंत्रों ने यदा कदा रेलवे वैगनों की अपर्याप्त उपलब्धता के बारे में सूचित किया है ।

(ग) से (घ) सीमेंट उद्योग को की जाने वाली वैगनों की आपूर्ति पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है । जहां कहीं आवश्यक होता है, रेलवे, जो इस संबंध में फील्ड अधिकारियों को उपयुक्त हिदायतें जारी करता है, के साथ परामर्श करके वैगनोंकी कमी को दूर करने के लिये सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है ।

ग्रामीण निर्धनता

747. **श्री राम जेटमलानी :**
श्री रणजीत सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 मई, 1991 के "हिन्दू" में "चैक आन इन्फलेशन एलोन केन सोल्व रूरल पार्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान ग्रामीण मजदूरों की आय में वृद्धि हुई है ;

(ग) यदि हां, तो नब्बे के दशक में ग्रामीण मजदूरों की आय में कितने प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन ग्रामीण मजदूरों के जीवन-स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की भावी-नीति क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : (क) से (ङ) सरकार को समाचार पत्र में छपे उक्त समाचार के साथ साथ वाणिज्य और उद्योग मंडल के पी एच डी० हाउस द्वारा किये गये अध्ययन के निष्कर्षों के बारे में जानकारी है । ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के लिये अनेक उपाय किये जाने आवश्यक हैं । मुद्रा स्फीति पर रोक लगाना एक ऐसा ही आवश्यक उपाय है । ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिये उन्हें रोजगार, और आय के साधन उपलब्ध कराना आवश्यक है । इसे मद्देनजर रखते हुये गरीबी निवारण कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रामीण गरीबों को उनकी आय और जीवन स्तर में सुधार लाने के लिये उत्पादक स्वरूप की परिसंपत्तियां तथा रोजगार मुहैया कराने हेतु संयुक्त प्रयास किये जाते हैं ।

Finalisation of Eighth Five Year Plan

748. SHRI RAM JETHMALANI:
SARDAR JAGJIT SINGH AURORA:

Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Eighth Five Year Plan was to start from April, 1990;

(b) if so whether it is also a fact that even after almost two years, the Eighth Five Year Plan has not been finalised;

(c) if so, whether it is a fact that now it is proposed to start the Eighth Five Year Plan from April, 1992; and

(d) if so, by when the final decision is likely to be taken in this regard ?

THE MINISTER OF STATE (INDEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI H. R. BHARDWAJ): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Yes, Sir.

(d) It has been decided that the Eighth Plan will start from April, 1992.

केलकर समिति का गठन

745. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केलकर समिति का गठन कब किया गया था और इस समिति ने सरकार